



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

No. 161]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2004/आश्विन 9, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2004/ASVINA 9, 1926

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2004

सं. 1-29/2004-बी एंड सीएस.— भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खण्ड (के) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा (1) के उपखण्ड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल सं. 13-1/2004-आरईएसटीजी से निर्गत दिनांक 9-1-2004 की अधिसूचना सं. 39 [सं. का. आ. 44(अ) तथा 45 (अ)] के साथ पठित दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के पैरा (ii), (iii) तथा (iv) तथा, उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

- (i) यह आदेश "दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश 2004 (2004 का 6) कहा जाएगा।
- (ii) यह आदेश संपूर्ण भारत में लागू होंगे।
- (iii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

### 2. परिभाषा

- (क) 'ब्राडकास्टर' का आशय निजी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह सहित कई व्यक्ति, पब्लिक या कारपोरेट निकाय, फर्म या कोई संगठन या बाडी, जो ब्राडकास्टिंग सेवा प्रदान कर रही है, से है। इसमें उसके प्राधिकृत वितरण एजेंसियां भी शामिल हैं।

- (ख) 'ब्राडकास्टिंग सेवाओं' का आशय आम जनता तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पहुंचाने के इरादे से सभी प्रकार के चिह्न, सिग्नल, लेख, चित्र, बिम्ब तथा ध्वनि का स्पेस अथवा केबल से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक तरंगों का ट्रांसमिशन करना है और इसके सभी व्याकरणिक रूपान्तरण तथा सम्बद्ध अभिव्यक्ति तदनुसार इसमें शामिल होंगे।
- (ग) 'केबल आपरेटर' का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क से केबल सेवा मुहैया कराता है या अन्यथा, केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंधन को नियंत्रित कराता है या उसके लिए जिम्मेदार होता है।
- (घ) 'केबल सेवा' का आशय कार्यक्रमों का केबल द्वारा ट्रांसमिशन है। इसमें किसी ब्राडकास्ट टेलीविजन सिग्नल का केबल द्वारा रि-ट्रांसमिशन भी शामिल है।
- (ङ) 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' का आशय किसी ऐसी प्रणाली से है जिसमें मल्टीपल सब्सक्राइबर्स द्वारा प्राप्त करने के लिए क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ तथा एसोसिएट सिग्नल जनरेशन केबल सेवा प्रदान करने के लिए अभिकल्पित नियंत्रण तथा वितरण उपकरण हों।
- (च) 'प्रभार' का आशय उस दर (कर छोड़कर) से है, जो एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को 26 दिसम्बर, 2003 को किए गए लिखित/मौखिक करार के कारण देय है। 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद लिखित/मौखिक करार का सिद्धांत दर की सीमा के निर्धारण के लिए लागू किया जाना चाहिए।
- (छ) 'फ्री टू एयर चैनल' का आशय ऐसे चैनल से है जिसके लिए ब्राडकास्टर को केबल अथवा स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, जिन्हें वह आम जनता तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पहुंचाने का इरादा रखता हो, के माध्यम से अपने ऐसे रि-ट्रांसमिशन के लिए कोई शुल्क या भुगतान नहीं किया जाता है।
- (ज) 'मल्टी सिस्टम आपरेटर' का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो ब्राडकास्टर और/अथवा उनके प्राधिकृत एजेंसियों से ब्राडकास्टिंग सेवा प्राप्त करता है और जो उसे उपभोक्ताओं और/या एक या एक से अधिक केबल आपरेटर को रि-ट्रांसमिट करता है।
- (झ) 'पे चैनल' का आशय ऐसे चैनल से है, जिनके लिए ब्राडकास्टर को स्पेस अथवा केबल के माध्यम से आम जनता तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कार्यक्रम पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक तरंगों के रि-ट्रांसमिशन के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है।

### 3. टैरिफ

निम्न द्वारा देय प्रभार, कर छोड़कर

- (क) केबल सब्सक्राइबर से केबल आपरेटर,
- (ख) केबल आपरेटर से मल्टी सिस्टम आपरेटर/ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) और
- (ग) मल्टी सिस्टम आपरेटर से ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित)

‘फ्री टू एयर’ तथा ‘पे चैनल’ दोनों के मामले में 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद दर अधिकतम सीमा होगी।

परन्तु शर्त यह है कि, यदि कोई नया ‘पे चैनल’ जिसे 26.12.2003 के बाद शुरू किया जाता है अथवा कोई चैनल जो 26.12.2003 को फ्री टू एयर चैनल हो और जिसे बाद में ‘पे चैनल’ में बदला जाता है तो ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है और यदि नए चैनल की व्यवस्था स्टैंड अलोन आधार पर अलग से अथवा अलग नए समूह के रूप में की जाती है और नया चैनल किसी खास ब्राडकास्टर द्वारा 26.12.2003 को प्रदान किए जा रहे समूह में शामिल नहीं किया जाता है तो ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी नए चैनल की दरों तक की जा सकेगी। नए पे चैनल तथा वे चैनल जो 26.12.2003 को फ्री टू एयर चैनल थे, परन्तु बाद में पे चैनल बन गए उनके लिए दर इसी प्रकार के चैनलों के लिए 26.12.2003 को उपलब्ध दर के समान रहेगी।

इसके अलावा यदि कोई मल्टी सिस्टम आपरेटर अथवा केबल आपरेटर पे चैनलों की संख्या 26.12.2003 को दिखाए जाने वाले पे चैनलों की संख्या से कम करता है तो अधिकतम प्रभार को इसी प्रकार के पे चैनलों के लिए 26.12.2003 को लागू दरों को ध्यान में रखकर कम किया जाएगा।

### 4. रिपोर्टिंग की आवश्यकता

ऐसे नए चैनलों जिन्हें 26.12.2003 को शुरू किया गया अथवा किसी ऐसे चैनल, जो 26.12.2003 को फ्री टू एयर चैनल था और जिसे बाद में ‘पे चैनल’ बनाया गया, के ब्राडकास्टर प्राधिकरण का उन दरों के बारे में इस आदेश के अनुसूची I में सूचना देगा। यह सूचना इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि के अथवा नए चैनल के प्रारंभ होने या फ्री टू एयर चैनल के पे चैनल बनने, जो भी लागू हो, के सात दिनों के भीतर दी जाएगी।

### 5. निरस्तीकरण

15 जनवरी 2004 का टेलीकम्यूनिकेशन (ब्राडकास्टिंग एवं केबल) सर्विसेज टैरिफ आर्डर 2004 इसके संशोधनों सहित एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

## 6. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदेश को अनुलग्नक 'क' में इस आदेश को जारी करने के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन दिए गए हैं।

डॉ. हर्ष वर्धन सिंह, सचिव-सह-प्रधान सलाहकार

[विज्ञापन III/IV/142/04/असा.]

### अनुलग्नक 'क'

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने 15.1.2004 के टीटीओ के द्वारा 26 दिसम्बर 2003 को मौजूद दर को दरों की उस अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसे केबल सब्सक्राइबर केबल आपरेटर को, केबल आपरेटर मल्टी सिस्टम आपरेटर को और मल्टी सिस्टम आपरेटर ब्राडकास्टर को भुगतान करेगा।
2. बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें नए पे चैनलों के कीमत निर्धारण के तरीके तथा फुटकर कीमतों में उसके प्रभाव के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इसी प्रकार, उन चैनलों को 'पे चैनल' के बदलने के प्रभाव के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जो 26 दिसम्बर, 2003 को 'फ्री टू एयर' चैनल थे।
3. प्राधिकरण ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। चूंकि बाजार में नए चैनल आ रहे हैं इसलिए इन नए चैनलों के कीमत निर्धारण के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की जानी है। साथ ही, 15.1.2004 के टैरिफ आदेश द्वारा ग्राहकों को प्रदत्त सुरक्षा को भी बनाए रखने की जरूरत है। निर्धारित अधिकतम सीमा को कायम रखने के लिए यह निश्चय किया गया है कि 26.12.2003 के बाद शुरू किए गए 'पे चैनल' को 26.12.2003 को मौजूद चैनल समूह का भाग बनने के अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार का नियम उन चैनलों के लिए भी लागू किया जाएगा जो 26.12.2003 को 'फ्री टू एयर' चैनल थे, परन्तु बाद में जिन्हें 'पे चैनल' बना दिया गया। आशा की जाती है कि इससे आपरेटरों को और उनके माध्यम से उपभोक्ता को भी विकल्प मिलेगा।
4. इन नए चैनलों की पेशकश अलग-अलग या ऐसे चैनल समूह के रूप में की जाएगी जिनके लिए 15.1.2004 टैरिफ आदेश में अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रकार उन ग्राहकों के लिए जो नए 'पे चैनल' प्राप्त नहीं करते हैं, पहले से निर्धारित अधिकतम सीमा जारी रहेगी। जहां उपभोक्ता नए 'पे चैनल' प्राप्त करता है, उन मामलों में वह सीमा जिस तक ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है, वह नए चैनल की दरों तक सीमित रहेगी।
5. प्राधिकरण ने 26.12.2003 के बाद शुरू किए गए नए चैनलों अथवा उन चैनलों के लिए जो 26.12.2003 को 'फ्री टू एयर' थे और जो बाद में 'पे चैनल' बन

गए, के लिए अधिकतम कीमत सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया है। उपभोक्ता के लिए नए चैनल के प्रभार निर्धारित करना कठिन है क्योंकि इन कीमतों में काफी बड़ा अन्तर है और इन्हें लागत से सम्बद्ध करना भी कठिन है। इसके अलावा यह एक स्थानीय मुद्दा है जिसको केन्द्रीय रूप से विनियमित करना आसान नहीं है। सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कीमत भिन्न-भिन्न पद्धतियों से विभिन्न प्रणालियों पर आधारित की जाती हैं। इनमें से काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा यदि इन पर कार्रवाई करने का ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें उपभोक्ताओं को विकल्प दिया जाए तथा अंतःसंयोजन करार अधिक पारदर्शी बनाया जाए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सरकार को अलग से सिफारिशें भेजी हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्थितियों में 'एड्रेसिबिलिटी' का फ्रेमवर्क दिया गया है। बहरहाल इस बीच कीमतों का विनियमन किया जाना होगा। यह संशोधित टैरिफ आदेश ऐसे विनियमन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

6. इस प्रकार प्राधिकरण ने उन चैनलों के लिए जो 26.12.2003 को मौजूद थे, अधिकतम सीमा समाप्त नहीं की है। नए शुरू किए गए 'पे चैनल' और ऐसे 'फ्री टू एयर' चैनल, जिन्हें बाद में 'पे चैनल' बनाया गया, के बारे में प्राधिकरण आशा करता है कि इन चैनलों की दरें इसी प्रकार के चैनलों के लिए 26.12.2003 को उपलब्ध दर के समान रहेंगी। अतः प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि ब्राडकास्टर प्राधिकरण को इन चैनलों के प्रभार के बारे में इस आदेश की अनुसूची I में सूचना देंगे। यह सूचना इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि अथवा नए 'पे चैनल' के प्रारंभ होने या 'फ्री टू एयर' चैनल का 'पे चैनल' बनने, जो भी लागू हो, की तिथि के 7 दिन के भीतर दी जानी होगी। सूचना की समीक्षा के बाद यदि आवश्यक हुआ तो प्राधिकरण इस पर हस्तक्षेप करेगा।

7. प्राधिकरण ने इस पर भी विचार किया कि यदि कोई मल्टी सिस्टम आपरेटर अथवा केबल आपरेटर 26 दिसम्बर, 2003 को दर्शाए जाने वाले पे चैनलों की तुलना में संख्या कम भी कर सकता है, इस संबंध में प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि ऐसी स्थिति में अधिकतम प्रभार 26.12.2003 को इसी प्रकार के चैनलों की दरों को ध्यान में रखकर कम किया जाएगा। किसी भी प्रकार की शिकायत की स्थिति में यदि आवश्यक होगा तो प्राधिकरण हस्तक्षेप करेगा।

8. संदर्भ की सहूलियत के लिए 15.1.2004 के पूर्ववर्ती आदेश और इसके सभी संशोधनों को निरस्त करते हुए एक स्वतः स्पष्ट आदेश जारी किया गया है, परिणामस्वरूप अब जारी किया गया आदेश, सभी पूर्ववर्ती आदेशों। संशोधनों तथा स्पष्टीकरणों का स्थान लेगा।

## अनुसूची-I

26.12.2003 के बाद प्रारंभ हुए नए चैनल अथवा 'फ्री टू एयर' चैनलों का 'पे चैनल' बनने पर ब्राडकास्टर द्वारा ट्राई को दरों की रिपोर्टिंग का फार्मेट

(टेलीकम्यूनिकेशन (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवा (दूसरा) टैरिफ आदेश 2004 की धारा 4 देखें)

1. (क) चैनल का नाम  (ब) चैनल की किस्म (जैसे की मनोरंजन, खेलकूद, सिनेमा आदि)	
2. (क) चैनल की भाषा  (ख) लक्षित लोग (राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, यदि क्षेत्रीय हो तो राज्य का उल्लेख हो )	
3. क्या चैनल पूरे देश में पे चैनल है या देश के किसी भाग में (राज्यों का उल्लेख यदि देश के किसी भाग में हो)	
4. (क) क्या यह एक अलग चैनल होगा या चैनल समूह का एक चैनल (ख) यदि समूह से सम्बद्ध हो तो अन्य चैनलों का नाम (ग) समूह में चैनल के मालिक का नाम	
5. (क) चैनल की दर, यदि अलग चैनल के रूप में प्रस्तुत हो (ख) चैनल में चैनल दर	
6. (क) समूह दर, यदि समूह के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है (ख) समूह में शामिल चैनलों के मालिकों के बीच राजस्व की हिस्सेदारी	
7. (क) संभावित विज्ञापन राजस्व (ख) यदि चैनल एफटीए चैनल में मौजूद है, पिछले तीन वर्षों में राजस्व	
8. उपभोक्ता टैरिफ पर संभावित प्रभाव	

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2004

**No. 1-29/2004-B&CS.**—In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section (2) and paras (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 read with the Notification No. 39 [(S.O. No. 44(E) and 45 (E) ] dated 09-01-2004 issued from file No. 13-1/2004-Restg. by the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

1. Short title, extent and commencement:

- i. This Order shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004".( 6 of 2004)
- ii. The Order shall be applicable throughout the territory of India.
- iii. The Order shall come into force on the date of its notification in the Official Gazette.

2. Definitions:

- (a) **"broadcaster"** means any person including an individual, group of persons, public or body corporate, firm or any organization or body who/which is providing broadcasting service and includes his authorized distribution agencies;
- (b) **"broadcasting services"** means the dissemination of any form of communication like signs, signals, writing, pictures, images and sounds of all kinds by transmission of electro magnetic waves through space or through cables intended to be received by the general public either directly or indirectly and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
- (c) **"cable operator"** means any person who provides cable service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of a cable television network;

(d) “**cable service**” means the transmission by cables of programmes including re-transmission by cables of any broadcast television signals;

(e) “**cable television network**” means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation, control and distribution equipment designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;

(f) “**charges**” means and includes the rates (excluding taxes) payable by one party to the other by virtue of the written/oral agreement prevalent on 26th December 2003. The principle applicable in the written/oral agreement prevalent on 26th December, 2003, should be applied for determining the scope of the term “rates”

(g) “**free to air channel**” means a channel for which no fees is to be paid to the broadcaster for its retransmission through electromagnetic waves through cable or through space intended to be received by the general public either directly or indirectly ;

(h) “**multi system operator**” means any person who receives a broadcasting service from broadcaster and/or their authorized agencies and re-transmits the same to consumers and/or re-transmits the same to one or more cable operators;

(i) “**pay channel**”, means a channel for which fees is to be paid to the broadcaster for its retransmission through electromagnetic waves through cable or through space intended to be received by the general public either directly or indirectly.;

### 3.Tariff:

The charges , excluding taxes, payable by

- (a) Cable subscribers to cable operator;
- (b) Cable operators to multi system operators/broadcasters (including their authorised distribution agencies); and
- (c) Multi system operators to broadcasters (including their authorised distribution agencies)

prevalent as on 26th December 2003 shall be the ceiling with respect to both free-to-air and pay channels.



Provided that if any new pay channel(s) that is/are introduced after 26-12-2003 or any channel(s) that was/were free to air channel on 26-12-2003 is/are converted to pay channel(s) subsequently, then the ceiling referred to as above can be exceeded, but only if the new channel(s) are provided on a stand alone basis, either individually or as part of new, separate bouquet(s) and the new channel(s) is/are not included in the bouquet being provided on 26.12.2003 by a particular broadcaster. The extent to which the ceilings referred to above can be exceeded would be limited to the rates for the new channels. For the new pay channel(s) as well as the channel(s) that were free to air as on 26.12.2003 and have subsequently converted to pay channel(s) the rates must be similar to the rates of similar channels as on 26.12.2003:

Provided further that in case a multi system operator or a cable operator reduces the number of pay channels that were being shown on 26.12.2003, the ceiling charge shall be reduced taking into account the rates of similar channels as on 26.12.2003.

#### 4. Reporting Requirement

The broadcasters of such new pay channel(s) that have been introduced after 26-12-2003 or of any channel(s) that was a free to air channel on 26-12-2003 is/are converted to a pay channel subsequently, shall furnish to the Authority information in respect of charges for these channels in Schedule I of this Order. This information shall be furnished within seven days of coming into force of this order or the launch of new pay channel(s)/conversion of free to air channel (s) to pay channels, whichever is applicable.

#### 5. Repeal

The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff Order 2004 dated 15th January 2004 along with its amendments is hereby repealed.

#### 6. Explanatory Memorandum

Annex A to this order contains an Explanatory Memorandum for the issue of this Order

Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy.-Cum-Principal Advisor

[ADVT. III/IV/142/04/Exty.]

296697/14 3

**Annex A****Explanatory Memorandum**

1 The TRAI vide TTO dated 15.1.2004 had specified as ceiling the rates at which the charges will be paid by the cable subscribers to cable operators, by the cable operators to multi system operators and the multi system operators to broadcasters, as those prevailing on 26<sup>th</sup> December, 2003.

2 A number of representations have been received seeking clarification on the manner in which new pay channels can be priced and the impact on retail prices. Similarly, clarifications have been sought on the impact of conversion to pay channels of channels that were free-to-air on 26<sup>th</sup> December, 2003.

3 This issue has been carefully considered by the Authority. Since new channels will be coming into the market a mechanism has to be provided for pricing of these new channels. At the same time, there is a need to conserve the protection provided to the consumers by the Tariff Order dated 15.1.2004. To maintain the sanctity of the ceiling, it has been decided that pay channels launched after 26.12.2003 should not be allowed to become part of bouquet of channels being provided on 26.12.2003. A similar rule would apply for those channels that were free-to-air on 26.12.2003 and later convert to pay. It is expected that this would give choice to the operators and through them to the consumers.

4 These new pay channels may be offered individually or as a bouquet of channels which are not covered by the ceiling specified by the tariff order dated 15.1.2004. Thus for those consumers who do not get the new pay channels the ceilings already prescribed would continue. Where the consumers get the new pay channels, the extent to which the ceilings referred to above can be exceeded would be limited to the rates for the new channels.

5. The Authority has considered the question of fixing a ceiling price for new pay channels that have been introduced after 26-12-2003 or for any channels that was a free to air channel on 26-12-2003 is subsequently converted to a pay channel. Fixation of prices charged for new pay channels to consumers is difficult because of large variations of these prices and of the difficulty in linking these to costs. Further this is a localized issue which is not easily amenable to centralized regulation. Prices in different parts of the country are based on different systems using different methodologies for fixing the subscriber base. Many of these problems will get resolved if addressability is introduced, giving consumers choice and making the interconnection agreements more transparent. TRAI has separately sent recommendations to the government which, inter alia, provide for a framework for transition to addressability in different situations. However, in the interim period prices will have to be regulated. This revised tariff order provides the framework for such regulation.

6. Thus the Authority has not lifted the ceiling for the pay channels that existed as on 26.12.2003. For the new pay channels introduced and the free to air channels converted to pay thereafter, the Authority expects that the rates for these channels would be similar to the rates prevalent on 26.12.2003 for similar channels. The Authority has therefore decided that broadcasters would furnish to the Authority information in respect of charges for these channels in the Schedule I of this Order. This information shall be furnished within seven days of coming into force of this order or the launch of new pay channels /converted Free to Air Channels to pay channels, whichever is applicable. After reviewing the information, the Authority would intervene in the matter, if necessary.

7. The Authority has also considered the issue regarding ceiling charges in case a multi system operator or a cable operator gives lesser number of pay channels compared to those shown on 26<sup>th</sup> December, 2003. The Authority has decided that in this case the ceiling charge shall be reduced taking into account the rates of similar channels as on 26.12.2003. In case of any complaint, the Authority would intervene in the matter, if necessary.

8 For ease of reference a self contained order has been issued repealing the earlier order dated 15.1.04 and all its amendments. Consequently the order now issued would supersede all previous orders, amendments and clarifications.

**Schedule I**

**Format for Reporting Rates by Broadcasters to TRAI for New Pay Channels  
Launched or Converted Free To Air Channel to Pay Channels after 26.12.2003**  
( Refer Section 4 of The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second)  
Tariff Order 2004

1. a) Name of the Channel  b) Genre of Channel (eg. Entertainment, Sports, Movies etc.)	
2. a) Language of Channel  b) Target Audience ( National or Regional, if Regional, specify state(s) )	
3. Whether channel is a pay channel in the whole of the country or only in part of the country. ( Specify states if pay in part of the country)	
4. a) Is it being offered as individual channel or bouquet of channel  b) If bouquet, name other channels  c) Name of owners of channels in the bouquet.	
5 a) Rate of channel, if offered as individual channel  b) Rate of channel in Chennai	
6 a) Rate of bouquet if offered as part of the bouquet  b) Revenue share arrangement between owners of channels in the bouquet	
7 a) Expected Advertisement Revenue  b) If channel is existing FTA channel, revenue for last three years	
8 Likely Impact on Consumer Tariff	